महाराष्ट्र ग्रीन बिल्डिंग अभियान में अग्रणी; पर्यावरण के क्षेत्र में सरकारी इमारतों के मूल्यांकन के लिए गृह परिषद के साथ मिलाया हाथ

– 300 भवनों का किया जा चुका है मूल्यांकन, 525 भवनों का मूल्यांकन किया जाना शेष

– गृह काउंसिल ग्रीन बिल्डिंग्स के मूल्यांकन के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को करेगा प्रशिक्षित

– श्री नितिन गडकरी द्वारा मौजूदा भवनों के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए गृह के नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए

नागपुर, 14 जून, 2019: भारत की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग निकाय गृह काउंसिल ने महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी–गृह ग्रीन बिल्डिंग पहल के दूसरे चरण की शुरूआत के लिए महाराष्ट्र सरकार, रीजनल चीफ इंजीनियर्स और लोक निर्माण विभाग के साथ छह आपसी समझौते पत्र (एमओयू) पर आज हस्ताक्षर किए। इस एमओयू में गृह की मौजूदा बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के मानदंडों के आधार पर 525 सरकारी इमारतों की रेटिंग करने के साथ ही पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण शामिल है। इस पहल के पहले चरण में 300 मौजूदा सरकारी इमारतों को रेटिंग दी गई है। महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है, जिसने अपने मौजूदा और बनने वाले बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर ग्रीन रेटिंग सिस्टम में बदलने, अपने अधिकारियों के भवन निर्माण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षित करने की प्रतिबद्धता जताई है और ग्रीन कार्यप्रणाली को अपनाने के लिए बिल्डरों को प्रोत्साहन की पेशकश की है। पीडब्ल्यूडी में गृह का एक प्रकोष्ठ है जो अधिकारियों की क्षमता को ग्रीन बिल्डिंग मूल्यांकनकर्ता के रूप बनने में मदद करता है और इस तरह से शहरी क्षेत्रों में हरियाली की प्रक्रिया में तेजी लाता है।

नागपुर में **महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग** के सहयोग से आयोजित एक दिवसीय **10वें रीजनल गृह सम्मेलन** में **माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्री श्री नितिन गडकरी** की उपस्थिति में एमओयू पर आज हस्ताक्षर किए गए। श्री गडकरी ने इस मौके पर संसाधन दक्षता बढ़ाकर उनका स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए भवनों को बनाने के दौरान टिकाऊ कार्यप्रणालियों को एकीकृत करने की खातिर नीतिगत दिशा–निर्देश भी जारी किए।

इस मौके पर **माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्री श्री नितिन गडकरी** ने कहा, *''इमारतों के जरिए काफी ऊर्जा खपत और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ग्रीन बिल्डिंग्स जीवन को दीर्घायु बनाने, उत्पादकता में सुधार लाने तथा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने में योगदान करती हैं। मैं पर्यावरण अनुकूल भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए जाने वाले इस परिवर्तनकारी प्रयास के रूप में उत्कृष्ट कदम उठाने के लिए गृह काउंसिल को बधाई देता हूं।''*

सम्मेलन में पीडब्ल्यूडी–गृह ग्रीन बिल्डिंग पहल के पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने का जश्न भी मनाया गया। पहले चरण में गृह ईबबी (मौजूदा बिल्डिंग) रेटिंग प्रणाली के मानदंडों पर 300 मौजूदा सरकारी भवनों की रेटिंग के लिए 16 जनवरी, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। नवनतम परियोजना के तौर पर **'नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन'** को **गृह ईबी के तहत 4 स्टार रेटिंग** दी गई है।

पात्र परियोजनाओं को रेटिंग दी गई और इस गतिविधि के दौरान अनुकरणीय पहल प्रदर्शित करने वाले पीडब्ल्यूडी कर्मियों को व्यक्तिगत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर **गृह काउंसिल के सीईओ श्री संजय सेठ** ने कहा, *''इस पहल में महाराष्ट्र सरकार के साथ भागीदारी कर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह देखकर खुशी हुई कि राज्य शहरी निर्मित वातावरण में बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। गृह परिषद के साथ साझेदारी में लोक निर्माण विभाग के नेतृत्व में पहले चरण में इस छोटी सी पहल ने सालाना करीब 2721 टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद की है, जो सड़कों से 600 वाहनों को हटाने के बराबर है।''*

'निर्मित वातावरण के लिए बदलाव की रणनीतियों' के केंद्रीय थीम पर आधारित इस सम्मेलन में सार्वजनिक भवनों में स्थायित्व की पहल को शामिल करने के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसे बहु–हितधारक साझेदारी शुरू करने, ज्ञान साझा करने और सरकार, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों, वास्तुकला, इंजीनियरिंग एवं निर्माण प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के बीच एक मंच के रूप में काम करने का अवसर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था।

पीडब्ल्यूडी–गृह ग्रीन बिल्डिंग पहल के पहले चरण के पूरा होने पर प्रगति को दर्शाती हुई तालिका :

बिल्डिंग का प्रकार	क्षेत्र	प्रस्तावित भवनों की संख्या	कुल भवन	रेटिंग	
			पंजीकृत	पूरा हुए	काम चल रहा है
नई बिल्डिंग (गृह)	नागपुर	101	84	1	83
	अमरावती	36	19	0	19
	औरंगाबाद	21	20	0	20
	नाशिक	0	0	0	0
	पुणे	36	25	1	24
	मुंबई	4	4	0	4
	कोंकण	3	3	0	3
	कुल	**201**	**155**	**2**	**153**
मौजूदा बिल्डिंग (गृह ईबी)	नागपुर	91	91	52	39
	अमरावती	30	30	28	2
	औरंगाबाद	37	37	28	9
	नाशिक	59	59	34	25
	पुणे	43	43	39	4
	मुंबई	12	12	7	5
	कोंकण	28	28	13	15
	कुल	**300**	**300**	**201**	**99**

गृह काउंसिल के बारे में

गृह काउंसिल एक स्वतंत्र, गैर–लाभकारी संस्था है जिसका गठन द एनर्जी एंड रिर्सोसेस इंस्टीट्यूट (टेरी) और नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप किया गया है, जिसका मकसद टेरी द्वारा विकसित स्वेदशी रेटिंग प्रणाली, जिसे एमएनआरई की ओर से भारत में ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के तौर पर अपनाया गया है, को बढ़ावा देना और उसका संचालन करना है। इसके तहत् एक टूल्स पूर्व निधारित मानदंडों के एक सेट के आधार पर इमारत के प्रदर्शन और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करता है और एक से पांच स्टार के बीच रेटिंग प्रदान करता है। गृह **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के लिए भारत के **'राष्ट्रीय निर्धारित योगदान'** के तहत् जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन रणनीति का एक हिस्सा है।

संपर्क:
एडलमैन – आशिता कुलश्रेष्ठ
Ashita.kulshreshtha@edelman.com
मोबाइल: 9919333066